देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 27.11.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखण्ड ए.आई. मिशन–2025 नीति लॉन्च की। ए. आई. का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने पर दिया जोर।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालन और सब्जी उत्पादन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सत्रह करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।
- शिक्षा विभाग दिसंबर के पहले सप्ताह से आउटसोर्स के माध्यम से 2 हजार 364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा; क्षेत्रवार स्थानीय युवाओं को भर्ती में दी जाएगी प्राथमिकता।
- और, देहरादून में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिये ज़िलाधिकारी सविन बंसल ने तय समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

उत्तराखंड ए.आई मिशन–2025 नीति

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उत्तराखण्ड ए.आई. मिशन–2025 की नीति लॉन्च की। उन्होंने कहा कि तकनीक आज विकास की मुख्य शक्ति है और इसके बिना समावेशी तथा सतत विकास संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मिशन सैटेलाइट और डेटा आधारित तकनीक की मदद से दैनिक जीवन की समस्याओं का रियल टाइम समाधान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

डिजिटल विभाजन और नैतिकता से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ए.आई. का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने तकनीक आधारित शोध और स्टार्टअप्स को विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नितेश झा ने ए.आई. मिशन का प्रस्तुतीकरण दिया और बताया कि यह नीति भारत सरकार की ए.आई. पॉलिसी के अनुरूप है तथा उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मिशन के उद्देश्यों, प्राथमिक क्षेत्रों और क्रियान्वयन रणनीति पर जानकारी साझा की गई।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के शुभारंभ में शामिल हुए, जहां उन्होंने सहकारिता और पर्यटन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालन और सब्जी उत्पादन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत लगभग सत्रह करोड़ रुपये और एन.आर.एल.एम समूहों को 75 लाख पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए राज्य में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियाँ डिजिटल प्रणाली से कार्य कर रही हैं और बड़ी संख्या में समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में उत्तराखंड राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है।

श्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड में सहकारिता को मजबूत करने के लिए नई प्राथमिक कृषि ऋण समिति, डेयरी और मत्स्य समितियाँ गठित की गई हैं और किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज–मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनता से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील भी की।

समीक्षा

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्य को मिलने वाली विशेष सहायता योजना और विभागों में चल रहे सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा के भीतर लागू किए जा सकने वाले सभी सुधारों को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने वाले विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग अपने–अपने मंत्रालयों से लगातार संपर्क में रहें और केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट व वित्तीय सहायता का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने वित्त और नियोजन विभाग के साथ समन्वय कर विशेष सहायता योजना के अधिकतम लाभ के लिए काम करने को कहा।

बैठक में परिवहन विभाग को 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन सुधारों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं, राजस्व विभाग को भूमि सुधार से जुड़े रिफॉर्म्स को समयबद्ध तरीके से लागू करने को कहा गया। उन्होंने यह भी बताया कि विभागों को जारी होने वाला राज्यांश अगले दो दिन में जारी कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों से योजना का अधिक लाभ लेने के लिए अधिक प्रोजेक्ट तैयार करने और नियमित समीक्षा करने को कहा।

सहायता राशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए अभियोजन विभाग को सहायता राशि दी जाएगी। इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और अभियोजन अधिकारियों को राज्य की स्थानीय बोलियों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही विभाग को डिजिटलीकरण के लिए भी सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी पुलिस लाइन देहरादून में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियोजन सेवा, न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सत्य की स्थापना और न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है।

मुख्यमंत्री ने विधि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, युवा अधिवक्ताओं के लिए मेंटरशिप और महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में चल रहे प्रयासों का भी जिक्र किया।

शिष्टाचार भेंट

पर्यटन, सिंचाई और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री महाराज ने हरिद्वार स्थित इकबालपुर नहर के निर्माण की अनुमति देने का अनुरोध किया, ताकि भगवानपुर और आसपास के क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की समस्या दूर हो सके। उन्होंने कहा कि नहर बनने से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा।

सतपाल महाराज ने उत्तर प्रदेश सरकार से हरिद्वार की दो नहरों को उत्तराखंड को हस्तांतरित करने और चंपावत के बनबसा बैराज की व्यापक मरम्मत के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध भी किया। इसके अलावा उन्होंने मुजफ्फरनगर के शुक्रताल घाट पर धार्मिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी सहयोग मांगा।

बैठक में सिंचाई और क्षेत्रीय विकास से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

भर्ती प्रक्रिया

शिक्षा विभाग दिसंबर के पहले सप्ताह से 2 हजार 364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह भर्ती जिला स्तर पर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी और सभी जिलों में पदों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर परिचारक और स्वच्छक तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद भी इसी प्रक्रिया से भरे जाएंगे।

भर्ती पूरी तरह आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की जाएगी, जिसमें मानदेय पन्द्रह हजार रुपये प्रति माह रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय में नियुक्ति होनी है, वहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवश्यक निर्देश

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने राजधानी में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिये आवश्यक निर्देश दिए हैं। ऋषिपर्णा सभागार में विभिन्न विभागों की सरकारी परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की प्रगति की समीक्षा में स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां भी अवैध अतिक्रमण है, उसे निर्धारित समयसीमा में हटाया जाए।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर वेतन रोकने, निलंबन और सेवा बाधित करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागों से अपनी परिसंपत्तियों का अद्यतन विवरण और अतिक्रमण की स्थिति रिपोर्ट दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा। जिन परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण नहीं है, उनके लिए प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में हरबर्टपुर क्षेत्र में लंबित मामलों पर धीमी प्रगति पर श्री बंसल ने नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि दो दिन में कार्रवाई न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।

सिल्वर एलीफेंट अवार्ड

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को संगठन के सर्वोच्च सम्मान 'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। लखनऊ राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड में स्काउट–गाइड आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए डॉ. रावत के प्रयासों की सराहना की।

सम्मान प्राप्त करने के बाद मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्काउटिंग युवा पीढ़ी में अनुशासन, एकता, सेवा–भाव और देशभक्ति की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में

स्कूलों और कॉलेजों में स्काउट–गाइड गतिविधियों का विस्तार तथा उसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर.....
प्रदेश में अब जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर दस लाख रूपये कर दी गई है– इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता प्रकाशित किया है।

उत्तराखंड में श्रम विभाग के प्रस्ताव को सशर्त मंजूरी– इस खबर पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है– महिलाओं को रात में नौकरी की छूट। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा– दुकानों, प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में भी कार्य कर सकेंगी महिलाएं।

राजधानी देहरादून में अवैध अतिक्रमण को लेकर दैनिक जागरण ने जिलाधिकारी के हवाले से लिखा– फैल रहा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का जाल, इसी पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है– सरकारी परिसंपत्तियों से तत्काल हटाएं अतिक्रमण।